श्रीराम अस्पताल की अवैध ओपीडी से मिल रही एक्सपायर्ड दवाइयां

धड़ल्ले से जारी हैं सभी प्रतिबंधित टेस्ट, ग्रीवेन्स कमेटी की लिखित कार्यवाही की हेराफेरी में अभी तक कार्रवाई नहीं

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबादः श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल में अवैध रूप से चलाई जा रही ओपीडी से दवाएं भी अब एक्सपायरी डेट (दवाई की खत्म हो चुकी तारीख) में दी जा रही हैं। किसी तरह का हादसा होने पर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, यह कोई नहीं जानता। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध अस्पताल के हालात इतने बुरे हो जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था।

मरीजों की जान से खिलवाड़

इस हफ्ते श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल की अवैध ओपीडी में कई मरीज या उनके तीमारदार विभिन्न बीमारियों के इलाज के सिलसिले में पहुंचे। ओपीडी में स्लिप पर डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी थीं, उसके बजाय मरीज को दूसरी महंगी दवा पकड़ा दी गई। मरीज जब दवा लेकर घर पहुंचा तो घर के लोगों ने दवा पर पड़ी तारीख देखी तो वो सारी दवाएं पिछले साल की निकलीं यानी वो दवाइयां एक्सपायर हो चुकी थीं। मेडिकल साइंस के अनुसार ऐसी दवाइयों का सेवन जानलेवा बन जाता है। लेकिन ओपीडी चला रहे लोगों के पास यह सब देखने का समय जैसे नहीं है। मजदूर मोर्चा के पास श्रीराम धर्मार्थ अस्पताल की ओपीडी से लिखी गई पर्ची और वहां से बेची गई दवाइयों के प्रमाण और वीडियो सुरक्षित हैं, जो किसी भी उचित जांच एजेंसी के मांगने पर उपलब्ध करा दी जाएंगी।

इसी अस्पताल से अब मरीजों को गलत टेस्ट लिखे जा रहे हैं और कराए जा रहे हैं। कई ऐसे भी टेस्ट लिखे और कराए गए हैं, जिन पर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन उन टेस्ट से कमाई खूब होती है, इसलिए उसे कैश किया जा रहा है।

हैरानी यह है कि दोबारा अस्पताल शुरू होने पर क्षेत्रीय ड्रग कंट्रोलर ने या उसके स्टाफ ने आकर यहां दी जा रही दवाइयों की पड़ताल नहीं की, जबकि बाकी अस्पतालों में उनका स्टाफ आये दिन पहुंचा रहता है। इस अवैध अस्पताल के संस्थापक सदस्य एस.एम. हाशमी भी इस अस्पताल की ओपीडी से एक्सपायरी दवाई दिए जाने पर हैरान है। हाशमी ने कहा कि आजतक इस अस्पताल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसे इस अस्पताल से गलत दवाई दी गई। गलत इलाज के लिए भी यह अस्पताल कभी बदनाम नहीं हुआ।

सब कुछ अवैध

शहर के बीचोंबीच बना यह अस्पताल नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद एमसीएफ इस अस्पताल की जमीन को वापस नहीं ले सका। हाई कोर्ट के आदेश पर एमसीएफ ने अस्पताल को सील कर दिया। बीच में जब कोरोना की दूसरी लहर फैली तो यहां कोविड सेंटर चलाने की आड़ में इसे कंवल खत्री गुट ने भाजपा विधायक सीमा त्रिखा की मदद से इसे खुलवा दिया। श्रीराम चैरिटेबल सोसाइटी के बैंक में रखे 12 लाख रुपये कोविड सेंटर शुरू करने पर फूंक दिए गए लेकिन अस्पताल और सोसाइटी को 12 रुपये की कमाई भी नहीं हुई। लेकिन सिर्फ अपना रुतबा दिखाने और इस संपत्ति पर कब्जे की नीयत से चंद लोगों ने गैंग बनाकर यहां राजनीति शुरू कर दी। पिछले दिनों यहां का मामला ग्रीवेन्स कमेटी में भी उठा। कमेटी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दोनों गुटों के लोगों की कमेटी बनाने और उन्हें जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया लेकिन डीसी दफ्तर में ग्रीवेन्स कमेटी की लिखित कार्यवाही को ही बदल दिया गया। जबकि ग्रीवेन्स कमेटी बैठक की कार्यवाही की वीडियो मौजूद है, जिसमें दुष्यंत निर्देश देते नजर आ रहे हैं लेकिन साजिश करके पूरी कार्यवाही रिपोर्ट ही गलत बना दी गई। दुष्यंत ने इस बैठक में कभी भी किसी भी मौके पर ओपीडी चलाने का निर्देश नहीं दिया था लेकिन इसके बावजूद यहां ओपीडी चलाई जा रही है।

मुस्कुराइए...यह हूडा की प्रॉपर्टी है, गलती से खरीद मत लेना

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद : सेक्टर 21 बी में यह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी - हूडा) की संपत्ति है। यहां पर या तो आवारा जानवरों का बसेरा है या फिर यहां गोबर के उपले पाथे जाते हैं। इसके अलावा रात के अंधेरे में कई अनैतिक गतिविधियां तक होती हैं। ड्रग्स की सप्लाई भी इस सुनसान जगह में की जाती है। हूडा ने करोड़ों रुपये खर्च करके यहां जमीन खरीदी थी और शॉपिंग सेंटर बनाया था लेकिन इस शॉपिंग सेंटर की दुकानों का रिजर्व प्राइस इतना ज्यादा था कि यहां किसी ने खरीदा नहीं। व्यापारिक नजरिए से यह जगह गलत लोकेशन पर है यानी यहां तक ग्राहक पहुंचेगा ही नहीं। इस वजह से लोगों ने यहां दुकानें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई।

हूडा की ऐसी तमाम साइटें हैं, जहां पर कब्जे हो रहे हैं। सेक्टर 45 और 46 में ऐसी जगहों पर हूडा ने सड़कें और फुटपाथ बनाकर जगह को छोड़ दिया है। उस पर दबंग अपने बाप का माल समझकर कब्जा कर रहे हैं। इन जमीनों की कीमत करोड़ों रुपये है। पिछले दिनों हूडा ने जो आक्शन का विज्ञापन निकाला था, उनमें भी कुछ प्लॉटों पर कब्जा है। ऐसे में लेने वाले को नतीजा भुगतना होगा। यानी हूडा ने खरीदार पर छोड़ दिया है कि वो खुद कब्जा खाली कराये। पाठकों को याद होगा कि हाल ही में मजदूर मोर्चा ने खबर प्रकाशित की थी कि बुढ़िया नाले और सेक्टर 46 के बीच हूडा की जमीन पर समुदाय विशेष के दबंगों ने किस तरह नई खोरी बसा दी है। यहां भाजपा नेताओं के संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं।

देखी-सुनी

खबरीलाल

पल्ले कुछ नहीं, छापे मारकर बता रहे हैं मैं हूं मंत्री

अनिल विज

हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने पिछले हफ्ते नगर निगम गुड़गांव में छापा मारा और कई सारे अफसरों, कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। अखबारों में खूब खबर छपी। विज को वाहवाही मिली। इसके बाद विज वापस चंडीगढ़ लौट गए। लेकिन मीडिया की सबसे बड़ी समस्या यह होती जा रही है कि वो इसके आगे-पीछे के सवालों के जवाब को नहीं तलाश करता। ऐसा तो नहीं है कि विज को कोई सपना आया और वो गुड़गांव में छापा मारने पहुंच गए। दूसरी बात वो पड़ोस के नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) छापा मारने क्यों नहीं आये, जहां हरियाणा के तमाम नगर निगमों के मुकाबले हालात बदतर हैं। हम आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है। दरअसल, नगर निगम गुड़गांव में जो भी नियुक्ति होती है, उसका फैसला या तो मुख्यमंत्री दफ्तर करता है या मुख्य सचिव कार्यालय करता है। मुख्य सचिव दफ्तर अपने प्यादे एस.एन. रॉय के जरिए अपना गेम करता है। विज के पास चपरासी वगैरह के तबादला का अधिकार है। ऐसा नहीं कि विज को या उनके रिश्तेदारों को गुड़गांव में काम नहीं पड़ते हैं। विज सिफारिश करते हैं लेकिन गुड़गांव के अधिकारी सीएम और मुख्य सचिव के नीचे किसी की सिफारिश पर काम ही नहीं करते। इस तरह बतौर स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज महा असफल नेता बन चुके हैं। लेकिन तथाकथित छापा मारकर वह मीडिया में सुर्खियां तो बटोर ही सकते हैं। इसलिए गुड़गांव नगर निगम का चुनाव उन्होंने सोच समझ कर किया, क्योंकि वहां पैसा नगर निगम की नालियों में बह रहा है। उन्हें लगा होगा कि गुड़गांव में छापा मारकर शायद वो यहां के अफसरों और कर्मचारियों पर रौब मारकर आगे काम करा सकेंगे। लेकिन इसका अंदाजा उन्हें जल्द हो जाएगा। अब दूसरा सवाल की विज एमसीएफ में छापा मारने क्यों नहीं आये। विज को पता है कि कंगाल नगर निगम में वो छापा भी मारेंगे तो उल्टा कर्मचारी, पार्षद पैसे का रोना रोएंगे। ऐसे में उनके छापे की बजाय मीडिया में यह छपेगा कि विज को एमसीएफ के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर घेर लिया। ऐसे में विज ने खुद को किसी मुसीबत में डालने की बजाय गुड़गांव को सॉफ्ट टारगेट पर रखा। देखते हैं कि विज एमसीएफ में आने की हिम्मत कब दिखाते हैं।

किसका एजेंट है चीफ इंजीनियर

एमसीएफ का चीफ इंजीनियर रामजी लाल जब यहां नियुक्त किया गया था तो अपने ईमानदारी के ढोल खुद ही पीटता था। लेकिन वक्त बीतने के साथ वो अब ठेकेदारों का एजेंट बन गया है। वो यह तक बताता था कि लंच में वो घर से लाई दो रोटी खाकर गुजारा कर लेता है। लेकिन अब रोजाना उसके लिए लंच में पैक्ड फूड (ब्रांडेड डिब्बाबंद खाना) का इंतजाम रहता है। उसको यह तक नहीं पता कि कौन सा जेई या एसई, एक्सईएन या इंजीनियरिंग विंग का स्टाफ रोजाना इस खाने को मंगवाता है। लेकिन अब मूल मुद्दे के बारे में आपको बताते हैं। चीफ इंजीनियर के दफ्तर में एक पत्रकार पहुंचा, जिसे चीफ इंजीनियर नहीं जानता था। लेकिन उसके पास पहले से एक ठेकेदार बैठा हुआ था और चीफ इंजीनियर मोबाइल पर एकाउंट्स ब्रांच के किसी अफसर से विनती कर रहा था कि इस ठेकेदार की पेमेंट करना है। उसने कहा कि सब व्यवस्था हो जाएगी। आप चिन्ता न करो। ठेकेदार को अर्जेंट पैसे की जरूरत है, इसलिए पेमेंट जल्दी चाहिए। मैं मैडम (कमिश्नर गरिमा मित्तल) से बात कर लूंगा। वो मुझसे बाहर नहीं हैं। चीफ इंजीनियर को बाद में ध्यान आया कि कोई और भी सामने बैठा है। उस पत्रकार से चीफ इंजीनियर ने काम पूछा। पत्रकार ने अपना परिचय छिपा लिया और बताया कि सैनिक कॉलोनी से आया हूं। मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। चीफ इंजीनियर ने उसे जबानी आश्वासन देकर विदा कर दिया। पत्रकार बेचारा अपने अखबार में खबर तो नहीं लिख सका लेकिन उसने खबरीलाल को यह जानकारी बातचीत के दौरान दे दी कि एमसीएफ का चीफ इंजीनियर किस तरह की हरकतें और भ्रष्टाचार फैला रहा है। कहा जा रहा है कि हाल ही में इंजीनियरिंग विंग के कई घोटालों में यह शामिल है लेकिन ऊपर से इतना मीठा बना रहता है कि जैसे राजा हरिश्चन्द्र के बाद इसी ने जन्म लिया है।

चेतना पांडे की जब जागी चेतना

चेतना पांडे फरीदाबाद में भाजपा की नेता हैं। भाजपा में मशहूर होने के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। बेचारी दो फ्लेक्सी बोर्ड लेकर सेक्टर 28 में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर के घर के बाहर किसी खंभे की तलाश में जूझती हुई मिलीं। उन्हें कोई खंभा खाली ही नहीं मिल रहा था, जिस पर वो अपना बोर्ड लगा देतीं। जिस लड़के को वो बोर्ड लगाने के लिए लाईं थीं, उससे मिन्नतें कर रही थीं कि किसी और नेता का बोर्ड इधर-उधर करके या नीचे टपका कर मेरा बोर्ड लगा दे। लड़का तैयार नहीं था। उसने कहा कि जिसका बोर्ड हटेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। मैडम आप इन लोगों को ठीक से नहीं जानते। यहां चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हैं, सब रेकॉर्ड होता है। खबरीलाल ने पसीने में लथपथ चेतना पांडे से पूछा कि मंत्री बने हुए तो काफी समय हो गया, अब क्यों बोर्ड लगाना चाहती हैं।

चेतना पांडे ने कहा कि बस, आप ये समझो कि चेतना अभी जागी है। अब हमें जरूरत पड़ रही है इसकी। बस, मंत्री जी की नोटिस में यह बोर्ड आ जाए तो काम बन जाएगा। पूरी कीमत वसूल हो जाएगी। जो पाठक सेक्टर 28 में केंद्रीय मंत्री के घर और दफ्तर के सामने से गुजरे होंगे कि वहां अब इतने फ्लेक्सी बोर्ड और होर्डिंग लग गए हैं कि ट्रैफिक के लिए बाधा बन रहे हैं और आने-जाने वालों का ध्यान भी भंग होता है। सेक्टर 28 की इस मुख्य रोड पर अब कोई खंभा बचा ही नहीं है, जहां छुटभैये नेताओं ने गूजर या उनके बेटे का स्वागत करते हुए बोर्ड न लगाए हों। हालांकि यह नगर निगम फरीदाबाद की विज्ञापन नीति का खुलेआम उल्लंघन है। एमसीएफ चाहे तो इसके लिए उन नेताओं से पैसे मांग सकता है लेकिन एमसीएफ भला ऐसी गुस्ताखी क्यों करेगा। मंत्री को चाहिए कि वो अपने घर या दफ्तर के पास कोई ऐसा कोना बता दें जहां लोग ऐसे बोर्ड या होर्डिंग लगाकर उनका गुणगान कर सकें, अन्यथा सेक्टर के निवासियों को इतने बोर्ड अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। कृष्णपाल के सामने वो भले ही कुछ न बोल पाएं लेकिन बुरा मुंह बनाने में देर नहीं लगाते।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06